

# मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान को पहला पुरस्कार

जयपुर। राज्य के माईंस विभाग ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी है के नेतृत्व में समूचे देश में माइनिंग सेक्टर में राजस्थान का परचम पहरा दिया है। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव माईंस, भूविज्ञान व पेट्रोलियम टी. रविकान्त को सोमवार को ओडिशा के कोणार्क में केन्द्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केन्द्रीय खान सचिव वी. कान्ताराव ने वर्ष 2023-24 में देश भर में एक्जप्लोरी परफार्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन का पहला पुरस्कार प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी है के मार्गदर्शन में प्रदेश में खनिज क्षेत्र में नई नीतियों से लेकर खोज खनन और राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की गई है। केन्द्र सरकार ने राजस्थान की उपलब्धि को अनुकरणीय परफार्मेंस बताया है।



कोणार्क में खान मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव माईंस टी. रविकान्त ने पुरस्कार प्राप्त किया।

पहली बार हुआ। नई सरकार आने के बाद तीन माह में ही मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन के योजनाबद्ध प्रयासों से राजस्थान यह उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि माईंस एवं भूविज्ञान विभाग की पूरी टीम द्वारा टीम भावना से किए गए समग्र प्रयासों से संभव हो पाया है।

इस उपलब्धि के लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों, माइनिंग सेक्टर के स्ट्रेक होल्डर्स सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी। रविकान्त ने बताया कि 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों में 22 माइनिंग लीज व 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की

■ **माइनिंग सेक्टर में राजस्थान ने समूचे देश में परचम फहराया**

गई। इनमें लाईम स्टोन के 22 ब्लॉक, आयरन और के 4 ब्लॉक और बेसमेटल के पांच ब्लॉक हैं। उन्होंने बताया कि मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में भी राजस्थान नया रिकार्ड रचने जा रहा है। निदेशक माईंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राजस्थान में खनिज खोज, खनन प्लांटों का डिनेलियेशन, भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी, अवैध खनन पर प्रभावी रोक व अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही आदि से विभाग को नई गति व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है।

कलाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया गया जिसमें नई सरकार के तीन माह के समय में ऑक्शन में तेजी आने से राजस्थान समूचे देश में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान एमएन डोलिंग और अधीक्षण सचिव अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा भी हिस्सा ले रहे हैं। दो दिवसीय नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मंगलवार को राजस्थान के प्रमुख सचिव माईंस टी. रविकान्त भी ऑक्शन और बेस्ट प्रेजेंटेशन पर प्रदर्शन देंगे।

# बजट के लिये सी.आई.आई. ने राज्य सरकार को सिफारिशें सौंपी

जयपुर। प्रो बजट मेमोरेंडम (पीबीएम) 2025 के लिए सीआईआई ने राज्य सरकार को सिफारिशें सौंपी। सीआईआई राजस्थान के वाईस चेयरमैन संजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव को राजीज राजस्थान की सफलता के लिए बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि एमओयु के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेप्स लेने पर धन्यवाद दिया। प्रो बजट मेमोरेंडम (पीबीएम) 2025 के लिए सीआईआई ने राज्य सरकार को निम्न सिफारिशें सौंपी। राज्य सरकार ने नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिफ्स) 2024 एवं 9 नई पॉलिसीज निकाली है। यह एक अपूर्वपूर्ण निर्णय है, मगर पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोगों में इसकी अवेयरनेस को कमी है। हालांकि सीआईआई अपने स्तर पर इसे उद्योगों को सुचित करता रहता है मगर हमारा मानना है कि सरकार के प्रतिनिधि सीआईआई के साथ राज्य के विभिन्न शहरों में इसकी पब्लिसिटी करें, जिसके इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा पहले भी होता रहा है। रिफ्स 2024 में क्लाज 6.3 में एमएसएमई के एक्सपॉन्शन पर कोई इन्सुल्टिव नहीं है। पेटक रिफ्स 2022 में एमएसएमई जू को एक्सपॉन्शन पर इन्सुल्टिव मिलता था। एमएसएमई जू हर स्टेट के रेवेन्यू एण्ड एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसी तरह

■ **राइजिंग राजस्थान की सफलता के लिए बधाई भी दी**

क्लाज 6.2 में रिफ्स 2022 को राहत दी गई है पर ऐसे कई उद्योग हैं जिनका प्रोडक्शन कोविड के कारण लॉबित हुआ था। इसलिए इस पर हमारा आग्रह है कि इस क्लाज में रिफ्स पॉलिसी 2019 को भी शामिल किया जाए। जैसे तो राज्य सरकार एमओयु के क्रियान्वयन के लिए उचित उपाय कर रही है पर हमारा मानना है कि इंडस्ट्री को इसमें साथ लेगे तो जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं सीआईआई इसमें उन मेंबर्स को मोटिवेट करके एमओयु के इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकता है। ऐसे बहुत सी इंडस्ट्री मेंबर्स होते हैं जिन्हें इसमें मदद की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री के नेट जीरो बाई 2070 को अचीव करने के लिए एन्वायरमेंटल, सोशियल और गवर्ननेंस (ईएसजी), और ग्रीन बिल्डिंग मुवमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है। लोगों में इसके अवेयरनेस को कमी है। हमारा मानना है कि सरकार ग्रीन बिल्डिंग्स, ईएसजी को प्रमोट करने एवं नेट जीरो बाई 2070 को अचीव करने के लिए उन्हें स्टॉप इड्यूटी में 1 प्रतिषत की छूट दें जो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते और खरीदते हैं। रिन्वेन्युएल एनर्जी को सरकार प्रमोट कर तो रही है परंतु राज्य के लोगों को इसका लाभ कम ही मिल रहा है। राज्य सरकार को के मांडल करियर

सेंटर की तर्ज पर कम से कम हर डिजिटल इंडक्वाइरि पर एक सेंटर खोलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस तरह से एक साल में कम से कम 50 हजार लोगों को अतिरिक्त एंपॉइंटमेंट मिलेगा। यदि रिकल को इंडस्ट्री के साथ क्लासमेट बनाया जाए तो गारमेंट्स, माइनिंग, टेक्सटाइल, हैडीक्राफ्ट में एक लाख लोगों को और रोजगार मिलेगा। नए कोर्सेज जैसे ए आई, स्मार्ट एप्लीकेशन और ड्रोन टेकनॉलॉजी, सोलर टेक्निकल, साइबर सिक्योरिटी के शॉर्ट टर्म क्लासेस को जरूरत है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात सरकारें पेटेंट और कॉपीराइट्स पर काफी काम कर रही हैं। वहीं के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर सेंटर बनाए गए हैं जो स्टार्टअप और इंडस्ट्री को पेटेंट दिलाते हैं मदद करते हैं और साथ में अवेयरनेस सेशन भी करते हैं। राज्य में इस अवसर की कमी है और नए स्टार्टअप एवं इंडस्ट्री को इसके बारे में बताने तथा इसका लाभ लेने की जरूरत है। राज्य सरकार को राजस्थान टेकनॉलॉजिकल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की जरूरत है। राज्य सरकार ने 13 फैसिलिटी सेंटर का गठन किया है जिससे का रुका हुआ अमाउंट मिल सके जो कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं बड़े उद्योगों में 45 दिन से ज्यादा रुका हुआ है। सीआईआई राजस्थान के वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख नितिन गुप्ता भी आज इसमें शामिल हुए।

फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने को लेकर अभ्यावेदन तय करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विभाग के सचिव और एसओजी को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को चार सप्ताह में तय करने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह एक सप्ताह में अपना अभ्यावेदन पेश करें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता डॉ. टीएन शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि आरपीएससी ने साल 2014 में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 29 पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें लिखित परीक्षा आयोजित कर अंतिम परिणाम मई, 2017 में जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी ने एक फर्म में कार्य करने का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया जबकि आरटीयू, कोटा से आरटीई में मिली जानकारी के अनुसार महिला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थी। दूसरी ओर कॉर्पोरेट मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित फर्म ने जुलाई, 2013 के बाद काम ही नहीं किया। इसी तरह एक अन्य महिला अभ्यर्थी डीआरडीओ में रिसर्च स्कॉलर थी, लेकिन इस भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र ही नहीं थे। इस संबंध में एसओजी और विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

## मोबाइल द दुपहिया चुराने वाले गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्टीचिंग और दुपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के तीन शांति बदमाशों को पकड़ा है। जिसमें में एक बाल अपचारी भी है। पुलिस आरोपियों के पास से चोरी की बाइक, एक लैपटॉप सहित स्टीचिंग के दौरान छिपी गए आठ मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वी गौतम ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्टीचिंग और दुपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के शांति बदमाश आसु उर्फ रवि गुर्जर निवासी सांगानेर जयपुर और नवीन उर्फ लुकका निवासी उच्चैन जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

# असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम में अनियमितता पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदी विषय के लिए आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 के परिणाम में अनियमितता बरतने पर आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अंजना चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने अदालत को बताया कि

आरपीएससी ने हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साल 2023 में भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी, लेकिन बाद में अंतिम उत्तर कुंजी ही जारी नहीं की। वहीं भर्ती के 214 पदों के मुकाबले तीन गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए 1612 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जबकि नियमानुसार पदों के तीन गुणा से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग ने असफल अभ्यर्थियों के अंक

भी सार्वजनिक नहीं किए। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक नहीं करना भर्ती की पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न करता है। मॉडल उत्तर कुंजी और लिए गए साक्षात्कार के हिसाब से याचिकाकर्ताओं को अंतिम परीक्षा परिणाम की मुख्य सूची में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन आयोग की मनमर्जी से उन्हें चयन से वंचित कर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

# पेयजल को लेकर नीति पेश करने के लिए आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीसलपुर बांध से पीने के पानी के लिए सप्लाई को वरीयता देने के मामले में राज्य सरकार को पॉलिसी ने पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल को खंडपीठ ने यह आदेश लोकेंद्र जैन की ओर से दायर जनिहत याचिका व प्रदेश में पेयजल की समस्या पर लिए एफ स्वप्रेरित प्रस्तावना पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि पानी कहाँ और कैसे सप्लाई

करना है, यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। वहीं इस संबंध में नीति बनाई जा रही है। इस साथ ही लोकेंद्र जैन की ओर से दायर याचिका सारहीन हो गई है। दूसरी ओर न्यायमित्र प्रतीक कालसीवाल ने कहा कि अभी तक ईआरसीपी से पानी नहीं मिला है। इस पर अदालत ने कहा कि वे चाहते हैं कि हर घर में पानी पहुंचाना चाहिए। अदालत इस मामले में पूर्व में रिट स्वीकार कर चुकी है, जबकि यह मुद्दा को जनिहत याचिका में उठाया गया है। इस पर एबी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में बनाई जा रही नीति पेश करने के लिए समय दिया

जाए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है। जनिहत याचिका में कहा गया कि बीसलपुर बांध के पानी की पहली प्राथमिकता पेयजल की होनी चाहिए। यदि पानी सरप्लास होता है तो उसे कृषि के उपयोग के लिए छोड़ा जा सकता है। वहीं यदि बांध के पानी को कृषि के लिए आरक्षित रखा गया तो आने वाले समय में जयपुर, अजमेर और टोंक के निवासियों के लिए पेयजल का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

## 'हाईकोर्ट प्रशासन अपना रुख करे स्पष्ट'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को कहा है कि शहर में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जेडीए की ओर तलाशी गई जमीनों को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल को खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेन्द्र मुलवानी की जनिहत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जेडीए अपने प्रस्ताव में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए नौदंड में सी बीधा जमीन और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में भूमि आरक्षित रखने की जानकारी दे चुका है, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन ने अभी तक उस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।

# डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको स्वयं को नहीं पता वे क्या बोल देते हैं : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता को अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है, फिर चाहे विपक्ष को क्या लग रहा है, यह उनकी सोच है। सदन में विपक्ष की भूमिका जैसी होगी, सत्ता पक्ष भी उसी लहजे में उसका जवाब देगा। डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उनको बाद में पता चलता है कि मैं क्या बोल दिया। ऐसे में भरो विपक्ष से आग्रह है कि विपक्षी नेताओं को बोलने से पहले अपने घर में झांक लेना चाहिए, दूसरों के घर में

- 'दिल्ली चुनाव को लेकर बयान देने से पूर्व पायलट पहले लीडरशीप के ढुलमुल रवैये को समझने का प्रयास करें'
- 'निर्दलीय विधायक क्षेत्र के विकास में अटका रहे हैं रोड़ा, विकास में राजनीति नहीं करनी चाहिए'

ताकझांक करना अच्छी आदत नहीं है। राठौड़ ने दिल्ली चुनावों को लेकर सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पायलट को थार रखना चाहिए कि दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी। पायलट को

अपने नेतृत्व और लीडरशीप के ढुलमुल नीति को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मानस बना लिया है। भाजपा अपने एजेंडे और

घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य कर रही है, भाजपा को जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतियों, सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति भाजपा में नहीं की जाती है। यहां जनता जो चाहेगी वो ही करेगा। जातिगत आधार पर कार्य नहीं किया जाता। भाजपा ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा कभी भी रेवडियां बांटने का कार्य नहीं करती। विपक्ष आनन फानन में रेवडियां बांटकर चुनावी लाभ लेने के लिए योजनाओं की घोषणा करता है, फिर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

# एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 204 किलो गांजे से भरा हुआ ट्रक-कंटेनर पकड़ा

उडीसा से तस्करी कर हरियाणा ले जा रहा था 2.50 करोड़ रु. का गांजा

जयपुर (कासं)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय, झुंझुनू जिले की चिड़ावा और सूरजगढ़ पुलिस ने 204 किलो गांजे से भरा ट्रक और कंटेनर पकड़ा है। पुलिस ने कई चंटों तक ट्रक का पीछा करने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर को दबोचा। कंटेनर की बांडी में बने गुप्त स्थान से 204 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। इस मामले में आरोपित ट्रक चालक सुभाष चन्द्र जाट (40) निवासी झोडू जिला चरखी दादरी (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अनुसार जब्त मादक पदार्थ गांजा की कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।



अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिग्शि एमएन ने बताया कि झुंझुनू जिले की चिड़ावा एजीटीएफ को सूचना मिली कि उडीसा से एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा आया है। सूचना को डबल कर चिड़ावा और सूरजगढ़ थाना पुलिस को अवगत कराया गया।

एम.एन. ने बताया कि जहां टीम की ओर से हरियाणा नंबर के ट्रक कंटेनर की तलाशी की गई। इस पर बगड की तरफ से आने की सूचना पर चिड़ावा पुलिस ने चिड़ावा बाईपास पर ट्रक कंटेनर को रूकवाने की कोशिश की। लेकिन चालक चिड़ावा कस्बे से होता हुआ मेंन हाईवे से ट्रक को सूरजगढ़ की तरफ भगाने लगा। सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस ने रघुनाथपुर टोल बूथ पर नाकाबंदी शुरू की गई। इसी दौरान कंटेनर चालक के ट्रक को स्टॉप की तरफ घुमा लेने की सूचना मिली। इस पर रघुनाथपुर टोल नाका से आगे स्यालू की तरफ से आने वाले रास्ते पर नाकाबंदी शुरू की गई। इसी बीच रघुनाथपुर से मण्डी सूरतगढ़ की तरफ वाले रास्ते पर कंटेनर आने की सूचना पर बरसिये कॉलेज के पास पावर हाउस मोड पर नाकाबंदी की गई। इस पर सूरजगढ़ की तरफ से कंटेनर आता दिखाई दिया। रूकवाने पर चालक

जानलेवा व खतरनाक तरीके से नाकाबंदी पर लगे जाब्तो पर ट्रक ऊपर चढाने की कोशिश कर रहा ट्रक को बुहाना रोड की ओर डिवाइडर पर चढाते हुए भागने लगा। इस पर चिड़ावा-सूरजगढ़ थाना पुलिस एवं एजीटीएफ की टीम ने ट्रक का पीछा किया तो चालक सूरजगढ़ कस्बे में कई वाहनों के टक्कर मारते हुए खतरनाक व जानलेवा तरीके से लगातार भागता रहा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से चालक को पुलिस ने ट्रक रोकने की कई बार हिदायत दी। लेकिन चालक लगातार भागता रहा। कंटेनर की रूकवाने के लिए दो बार सावधानी उद्वेग हुए बुहाना व सूरतगढ़ की तरफ से कोई वाहन व राहगीर आते हुए नहीं दिखाई देने पर खाली जगह होने पर जाखोद बाईपास तिराहे से पहले सर्विस पिस्टल से व्हाई फ्लाय कर भी चेतावनी दी गई। इसके बावजूद भी भी चालक कंटेनर को लगातार दौड़ाते हुए

गिरफ्तार हुआ था। जिसमें इसे 10 साल की कैद हुई थी। साल 2017 में बेल मिलने पर आरोपित फरार हो गया। आरोपित हरियाणा का उद्घोषित अपराधी है। जिसके ऊपर इनाम भी रखा गया है। पुलिस की टीम आरोपित से गहनता से पूछताछ कर रही है और इसके आपराधिक रिकार्ड के बारे में जानकारी ली जा रही है। इस कार्रवाई में एजीटीएफ पुलिस मुख्यालय के हेड कांस्टेबल मोहन लाल व कमल डामर एवं एजीटीएफ झुंझुनू एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल शशिकांत एवं कांस्टेबल अमित की विशेष भूमिका रही। टीम में एजीटीएफ पीएचक्यू से उपनिरीक्षक सुभाष तंवर, एएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, नरेंद्र, सुरेश, कांस्टेबल रतिराम व चालक सुरेश तथा झुंझुनू जिले से सीओ चिड़ावा विकास धिन्धवाल एवं एसएचओ सूरजगढ़ हेमराज शामिल थे।

# रबी सीजन 2025-26 में गेहूं खरीद हेतु सभी तैयारियां हो समयबद्ध रूप से पूरी : सुमित गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में गेहूं खरीद करने वाली सभी पांच एजेंसियों (एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड) के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। गोदारा ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने हेतु कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आगामी रबी सीजन में गेहूं के

■ 'खरीद प्रक्रिया में सुगमता हेतु संबंधित एजेंसियां उचित समन्वय के साथ काम करें'

समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पांच एजेंसियां एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ कार्य करें ताकि गेहूं खरीद से लेकर धुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अधिक उत्पादन की संभावना वाले क्षेत्रों में उचित चयन उपरत आवश्यकतापुसार

नए खरीद केंद्र खोले जाएं। इस हेतु अधिकारी जिलों के दौर कर खरीद केंद्र की जरूरत वाले स्थानों को चिन्हित करेंगे। गोदारा ने कहा कि मंडियों में खरीद के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतापुसार बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गिरदावरी की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही तो मंडियों में आवश्यक सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उचित प्रचार प्रसार के माध्यम से आगामी रबी सीजन में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को दी जाए। हेल्पलाइन के माध्यम से भी किसानों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं को प्रभावी रूप से साझा किया जाए।

बैठक में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने कहा कि रबी सीजन 2025-26 के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी भंडारण गृहों में उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि आगामी रबी सीजन की तैयारी के लिए राज्य सरकार के प्रबंध निदेशक सौरभ चौरसिया, तिलमसंघ के अध्यक्ष राधेश गुप्ता, राजफेड प्रबंध निदेशक नारायण सिंह, एफसीसीएफ के मधु शर्मा, नेफेड से, महेश सिंह रावत, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर सहित विभिन्न उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।